Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

ई–गवर्नेस और डिजिटलाइजेशन का मानव जीवन पर प्रभाव

डॉ0 राकेश कुमार मिश्रा

एसो0 प्रो0–भूगोल, डी0बी0एस0 कालेज , कानपुर,उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3, Issue 3
Page Number : 173-177

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 01 May 2020
Published : 30 May 2020

शोधसार – जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तब से मनुष्य किसी न किसी प्रकार के शासन व्यवस्था के अन्तर्गत रहा है। शासन द्वारा ही समाज पर नियंत्रण रखा जाता है और समाज व्यवस्था को संचालित करता हैं। शासन द्वारा ही मानव की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रमों को क्रियांवित किया जाता है। ई–गवर्नेस, आज सुशासन का पर्याय बन चुका है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत में ई–शासन की शुरूआत होती है– सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण से। डिजिटलाइजेशन के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लगा है। शासन एवं प्रशासन के कार्यों में खुलापन एवं पारदर्शिता आती है। सरकारी प्रतिष्ठानों एवं विभागों पर जनता का विश्वास बढ़ता है। बिचौलिए तथा दलालों की भूमिका समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ई–गवर्नेस (शासन) एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी काम–काज में पारदर्शिता के साथ सभी सेवायें एवं सुविधाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुॅचायी जा रही है।

मुख्य शब्द :– डिजिटलाइजेशन, सूचना और प्रौद्योगिकी, ई–गवर्नेस, कम्प्यूटरीकरण।

जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, तब से मनुष्य किसी न किसी प्रकार के शासन व्यवस्था के अन्तर्गत रहा है। शासन द्वारा ही समाज पर नियंत्रण रखा जाता है और समाज व्यवस्था को संचालित करता हैं। शासन द्वारा ही मानव की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जरूरतों को पूरा किया जाता है।नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रमों को क्रियांवित किया जाता है। लेकिन आज हम आधुनिक जटिल समाज में रह रहे हैं इसलिए शासन का संचालन भी जटिल हो गया है।शासन के संचालन को कैसे सहज, सरल एवं पारदर्शी बनाया जाये, यह एक पक्ष प्रश्न है।इस प्रश्न का उत्तर है – ई–गवर्नेस,–जो एक आधुनिक तकनीक युक्त उपाय है। जिसका आज लगभग हर देश प्रयोग कर रहा है।भारत में भी इसके अभिनव प्रयोग की शुरूआत हो चुकी है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ई–शासन या ई–गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रानिक शासन कहलाता है। संचार क्रांति के कारण आज ई–गवर्नेंस का सपना पूरा हो पा रहा है। संचार के साधन आज इतने विकसित हो गये हैं कि हम घर बैठे किसी भी प्रकार की कहीं की भी जानकारी हासिल कर सकते है। किसी भी कार्यालय, विभाग तथा दफ्तर से किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी बिचौलिये या तीसरे माध्यम के। कोई भी विभागाध्यक्ष एवं सरकारी प्रमुख एक जगह बैठकर सारी कार्यवाही एवं प्रगति का लेखा–जोखा ले सकता है। यह सब सम्भव हुआ है– इलेक्ट्रानिक संसाधनों यथा– इण्टरनेट, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, फेसबुक, सी0सी0टी0बी0, ई–मेल इत्यादि के कारण।

ई–शासन या ई–गवर्नेंस आज सुशासन का पर्याय बन चुका है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत में ई–शासन की शुरूआत होती है– सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण से। आज यह शुरूआत हर व्यक्ति के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है, जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। वास्तव में किसी भी सरकार अथवा शासकीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, आमजन तक सेवाओं को पहुँचाने में सुगमता और जनता से संवाद स्थापित करने की दिशा में किस ढंग से प्रयास कर रही है और कितना अपने प्रयास में सफल है। वर्ष 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई–शासन योजना के तहत पूरे देश मे साझा सेवा केन्द्र स्थापित किए गये हैं। ये साझा सेवा केन्द्र आम आदमी को सीधे तौर पर उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। देश भर में एक लाख से अधिक साझा सेवा केन्द्र अलग–अलग ब्राण्ड नाम से अपनी सेवायें दे रहे हैं।

ई–गवर्नेंस में डिजिटलीकरण का उपयोग करने से कोई भी काम कम समय में हो जाता है। इसमें काम तो कम्प्यूटर या लैपटाप द्वारा कराया जाता हे ,जो कहीं से भी हो जाता है। इससे कार्य या सेवा की कुशलता भी बढ़ जाती है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए सब्सिडी राशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा हो जाती है, इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लग जाता है। शासन एवं प्रशासन के कार्यों में खुलापन एवं पारदर्शिता आती है। सरकारी प्रतिष्ठानों एवं विभागों पर जनता का विश्वास बढ़ता है। बिचौलिए तथा दलालों की भूमिका समाप्त हो जाती है।

ई–गवर्नेंस में डिजिटलीकरण का उपयोग करके कार्य के लागत में कमी लायी जा रही है। सरकार का अधिकांश खर्च कागजों पर होता है। इसके अलावा सामान्य जनता को अपने घर से किसी सरकारी कार्यालय में आने– जाने मे बहुत समय एवं पैसा खर्च करना पड़ता है, इससे बचत होती है। सभी विभागों, स्कूलों तथा कालेजों में बायोमिट्रिक लग जाने पर कर्मचारियों की कामचोरी तथा अनुशासनहीनता पर अंकुश लग

सकेगा। सभी कर्मचारियों के बायोमिट्रिक उपस्थिति लेने से कर्मचारियों के उपर शासन का नियंत्रण लगेगा। स्कूलों तथा कालेजों में नकलविहीन परीक्षा कराने में सी0सी0टी0वी0 के कारण नकल पर अंकुश लग सकेगा। ये सभी प्रयास सरकार द्वारा एक बेहतर, पारदर्शी, जवाबदेह एवं विश्वसनीय शासन एवं प्रशासन देने के लिए किए जा रहे है। यह सब डिजिटलीकरण के कारण ही सम्भव हो पा रहा है।

इस प्रकार ई–गवर्नेस (शासन) एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी काम–काज में पारदर्शिता के साथ सभी सेवायें एवं सुविधाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुँचायी जा रही है। बहुत से लोगों को आफिसों के चक्कर लगाने से डर लगता था। वे भी अब बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। दफ्तरों, आफिसों तथा विभागों में कर्मचारियों को समय सीमा में बाधनें का कार्य किया है डिजिटलीकरण ने। साथ ही जनहित गारण्टी अधिनियम ने ई–शासन में तेजी ला दी है। जनहित के कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे सरकारी काम–काज में लेट–लतीफी और रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकेगा।

आज आयकर भरना, बिजली, पानी,फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बनवाना तथा इसका सत्यापन का काम इण्टरनेट के माध्यम से आनलाइन कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी न्यायलयों को भी आनलाइन नहीं जाना पड़ता है। सम्पत्ति की रजिस्ट्री, मकानों के नक्शे, खाता–खतौनी आदि सभी आनलाइन कर दिये गये हैं।

हालॉकि यह सही है कि शासन तथा प्रशासन के कार्यों में डिजिटलीकरण को अपनाने से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, देरी एवं विलम्ब पर अंकुश लगा है। लेकिन भारत में इसकी रफतार अभी धीमी है। भारत जैसे देश में इसकी सफलता के मार्ग में कई बाधाएं है, जैसे– पहली बाधा है– आधारभूत ढ़ाचों की कमी अर्थात भारत में अभी ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में इण्टरनेट एवं ब्राडबैंड सेवाओं का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो सका है। बिजली आपूर्ति की कमी तथा इण्टरनेट सेवाओं के धीमे चलने के कारण कार्यों में बाधाएं आती रहती है तथा अनवरत सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पैदा होती रहती है। गरीबी तथा मंहगाई के चलते अभी भी बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोप नहीं है। दूसरी बाधा है– जागरूकता की कमी। भारत में अभी भी शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। तब ऐसी स्थिति में डिजिटल साक्षरता की रफतार तो धीमी ही रहेगी।बहुत सारे अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति इण्टरनेट चलाने तथा इण्टरनेट पर उपलब्ध एप्प एवं पोर्टल के ज्ञान की सुविधा से वंचित है। इस प्रकार डिजिटल निरक्षरता एक बड़ी बाधा है, ई–शासन के लाभों को प्राप्त करने में । तीसरी बाधा है– साइबर अपराध अर्थात डाटा एवं सूचनाओं की चोरी अथवा गलत डाटा एवं सूचनाओं का प्रसारण। आज आए दिन फेक न्यूज से सोसल मीडिया भरे रहते हैं। सूचनाओं एवं डाटा का गलत तरह से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जैसे– भारत जैसे बहुआयामी, बहुजातीय तथा बहुधार्मिक देश में फेंक न्यूज तथा गलत सूचनाओं के द्वारा बड़ी आसानी से जातीय एवं साम्प्रदायिक दंगे करवाये जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनाओं एवं जानकारियों को शत्रुओं द्वारा भी हैक करके देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा किया जा सकता है। इसको रोकने के लिए अपेक्षित कानूनों की कमी है। जो थोड़े बहुत कानून बने भी हैं, उनकी आम जनता को जानकारी नहीं है। जागरूकता की कमी इसका प्रमुख कारण है।

लेकिन उपर्युक्त कमियों के बावजूद ई–गवर्नेंस के फायदे कम नही है। ई–शासन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे सरकारी काम–काज में तेजी आ गई है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आ गई है। सूचना के अधिकार कानून ने इस पारदर्शिता को और धार दे दिया है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकारी काम–काज के लागत में कमी आयी है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ा है, क्योकि सरकारी काम–काज अभी तक कागजों पर होते रहे हैं, जिस पर अत्यधिक धन खर्च होता था और काम भी देर से होते थे। लेकिन अब जब से इण्टरनेट के माध्यम से आनलाइन काम होने लगे हैं, तब से कागजी युग समाप्त होता जा रहा है और काम भी तेजी से होने लगे हैं। सरकारी काम–काज के खर्च में पर्याप्त रूप से बचत होने लगी है। ई–शासन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है। कागज उत्पादन के लिए अब पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं रह गई है। वृक्षारोपण में बृद्धि होने से पर्यावरण का संतुलन बेहतर हो रहा है। इसलिए ई–शासन को पर्यापरण का मित्र कहा जा सकता है।

ई–शासन का एक लाभ यह भी है कि इससे विभागों तथा कार्यालयों की जवाबदेही बढ़ी है। अब कोई भी सरकारी विभाग और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इस प्रकार ई–गवर्नेंस का जो उद्देश्य था कि सरकार और नागरिकों के बीच संवाद हो, सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिले तथा नागरिकों को डिजिटल बनाना, उसे बहुत कुछ हद तक हासिल कर लिया गया है।लेकिन अभी भी बहुत कुछ इस दिशा में किया जाना जरूरी है।

अतः यदि भारत में ई–गवर्नेंस के सपने को साकार करना है तो सबसे पहले आधारभूत ढ़ाचों को सुधारना होगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। डाटा एवं सूचनाओं की चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आतंकवादियों तथा अपराधियों के हाथ लगने से डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित रखने के बंदोबस्त करने होंगे। डिजिटल साक्षरता एवं कम्प्यूटर साक्षरता को एक जन आंदोलन के रूप में चलाने की जरूरत है, जिससे हर व्यक्ति तक न केवल इंटरनेट आदि की सुविधा पहुँचे बल्कि लोगों को इसके उपयोग करने की जानकारी भी मिले। इसके लिए इंटरनेट की गति को बढ़ाना होगा तथा ब्राडबैंड सेवाओं का देश के हर कोने तक विस्तार करना होगा। स्कूलों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता की शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सरकार के हर विभाग तथा प्रतिष्ठानों में इंटरनेट एवं आनलाइन की सुविधा को स्थायी रूप से बहाल करना होगा। तभी शासन एवं प्रशासन हर व्यक्ति के घर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा और सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हर

व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इन योजनाओ एवं कार्यक्रमों का जनता सीधे लाभ ले सकेगी। आज क्षण भर में एक फोन काल पर प्रसूति सहायता, महिलाओं की सुरक्षा तथा घायलों की चिकित्सा के लिए एंबुलेंस सेवा हाजिर हो जाती है, यह डिजिटलाइजेशन का कमाल है। आज न केवल शहरों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक जो आकस्मिक पुलिस सहायता सेवा उपलब्ध है, वह भी डिजिटलाइजेशन का ही परिणाम है। पुलिस प्रशासन को डिजिटलाइजेशन ने न केवल चुस्त–दुरूस्त किया है बल्कि ज्यादा संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाया है। आज 100 नंबर डायल करने पर पुलिस चौबीसो घंटे हाजिर है। इस प्रकार ई–गवर्नेंस का उद्देश्य जहॉ सुशासन देना है वहीं इसका सारा ताना– बाना डिजिटलाइजेशन पर निर्भर करता है। इसलिए डिजिटलाइजेशन के उपयोग को बेहतर बनाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://iasscore.in/national-issues/digital-india-programme-importance-and-impact,date-29/08/2018,04:02pm.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India,28/08/2018,11:25am.
3. https://www.thebetterindia.com
4. http://negd.gov.in
5. https://www.mygov.in/group/digital-india
6. https://www.quora.com